समाचार पत्रों की कतरनें

अप्रैल, 2026

हिमाचल दस्तक, दिनांक–02.04.2026

प्राइवेट व्हीकल की भी होगी ऑटोमैटिक टेस्टिंग

डिप्टी सीएम बोले- हर जिले में होगा ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर

विशेष संवाददाता ■ शिमला

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भविष्य में कमर्शियल व्हीकल के बाद प्राइवेट व्हीकल की पासिंग भी ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटरों के माध्यम से ही होगी। इस व्यवस्था को आने वाले समय में लागू किया जाएगा जिसके लिए राज्य के हर जिला में एक ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित होगा।

उन्होंने कहा कि अब जमाना बदल रहा है। वाहनों की पासिंग अभी तक मैनुअल होती है, मगर प्रदेश में अब 7 स्थानों पर ऐसे टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां पर ऑटोमैटिक तरीके से पासिंग होगी। पहली बार पास न होने वाले

■ पासिंग के लिए मिलेंगे दो मौके, तीसरी बार स्क्रैप में जाएगा वाहन

वाहनों के लिए दूसरा मौका मिलेगा और फिर तीसरी बार वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। सदन में विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 में कांगड़ा के उठाए मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी तक 7 स्थानों पर ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीएस) स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत निजी क्षेत्र कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब तथा सरकारी क्षेत्र में हरोली व नादौन में एटीएस को स्थापित किया जाएगा। इन स्टेशनों में 5 से 10 मिनट में वाहन परीक्षण किया जा सकेगा। साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी जिलों में ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ऑटोमैटिक सेंटर में लगातार दूसरी बार गाड़ी पास नहीं होती तो उसे स्क्रैप किया जाएगा। केवल सिंह पठानिया का कहना था कि जिला कांगड़ा में 1 एटीएस रानीताल में होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–03.04.2026

माउंट कार्मेल स्कूल की घटना के बाद बढ़ी सख्ती, सुरक्षा मापदंडों को बारीकी से परखा

पुलिस ने जांचे 382 स्कूल वाहन; 120 के चालान, 4 जब्त

हिमाचल दस्तक ■ ऊना

जिला ऊना पुलिस ने मार्च 2026 के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया। इस विशेष अभियान के तहत जिले भर में कुल 382 स्कूल बसों की गहन जांच की गई, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मापदंडों को बारीकी से परखा गया।

जांच के दौरान नियमों की अनदेखी सामने आने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 120 स्कूल बसों के चालान किए, जबकि 4 बसों को गंभीर खामियों के चलते जब्त कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के अनुसार स्कूल बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट, स्पीड गवर्नर, फायर सेफ्टी उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट ऐड बॉक्स तथा चालक के वैध दस्तावेजों की विशेष रूप से जांच की गई। साथ ही बसों में ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों के पालन पर भी कड़ी नजर रखी गई। यह अभियान हाल ही में माउंट कार्मल स्कूल की एक छात्रा की मौत के बाद और अधिक सख्ती के साथ चलाया गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने स्कूल वाहनों की नियमित जांच को प्राथमिकता दी है, ताकि

● नशे में वाहन चलाने वाले 46 चालकों पर भी कार्रवाई की

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इसके अलावा, पुलिस द्वारा जिले में लगाए गए विशेष नाकाबंदी अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। मार्च माह में कुल 46 वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में न बरतें लापरवाही : सचिन हिरेमठ

जिला पुलिस प्रमुख सचिन हिरेमठ ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें और विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्कूल बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की जांच और अधिक तेज की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों की नियमित जांच करवाएं और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–13.04.2026

सड़क हादसे रोकेगा 'ई-डार डिजिटल कवच'

हिमाचल में सड़क सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी पुलिस

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। राज्य भर में ई-डार (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटनाओं का न केवल पंजीकरण होगा, बल्कि उनके कारणों और पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समय रहते रोकथाम भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से मार्च माह तक तीन महीने में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पेश आए 529 सड़क हादसों में 242 लोगों ने जान गवाई है। इसके अलावा 837 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य ई-डार के जरिए इन आंकड़ों को जड़ से कम करना है।

यह प्रणाली दुर्घटना के समय, स्थान, कारण, वाहन और पीड़ित से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करती है, जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। डीआईजी टीटीआर संजीव गांधी ने कहा कि ईडार केवल रिपोर्टिंग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करता है। प्रदेश में शाम छह से नौ बजे तक डेंजर विंडो घोषित की गई है, इस समय सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे विंग के डीआईजी संजीव गांधी ने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन में शाम छह से नौ बजे का समय सबसे अधिक जोखिम वाला पाया गया है।

इसी कारण इस समयावधि में राजमार्गों पर विशेष इंटरसेप्टर वाहन और अतिरिक्त गश्ती दल तैनात किए गए हैं। आम लोगों के लिए ईडार के तीन बड़े फायदे हैं, जिसमें डिजिटल रिपोर्टिंग से सीधे मदद मिलेगी और 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना की जानकारी ईडार पर दर्ज होने पर पीड़ित को तुरंत कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

दुर्घटनाएं रोकने को कार्ययोजना

तकनीक, सख्ती और सुधार, शाम छह से नौ बजे तक सघन पुलिस गश्त, स्पीड कैमरों और अल्को-सेंसर से निगरानी, अवैध पार्किंग पर तुरंत कार्रवाई, खतरनाक पहाड़ी मोड़ों पर हाई-विजिबिलिटी साइन बोर्ड, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश, आज सतर्क, तो कल सुरक्षित, सतर्क रहें आज, जीवित रहें कल, रफ्तार रोमांच देती है, पर जान भी ले सकती है, धीरे चलें, पहाड़ गलतियां माफ नहीं करते।

The Tribune, Dated 23-04-2026

1st automated driving test facility at Haroli

₹9-crore sensor-based system promises transparent evaluation, online scheduling for applicants

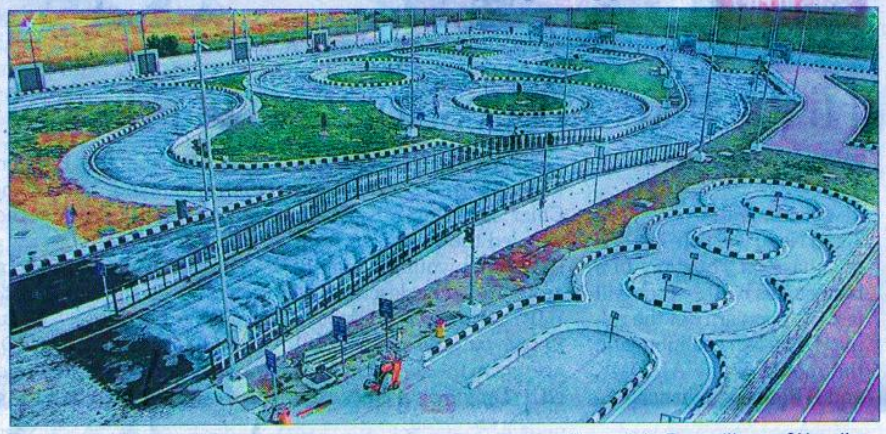

The newly inaugurated automated driving test track and traffic park in Rora village of Haroli.

dling, incline driving and manoeuvrability checks.

The Deputy Chief Minister highlighted that the entire system has been digitised, enabling applicants to book test slots online for greater convenience and efficiency. To further improve public access, an additional building with a waiting area will be constructed. In the next phase, the facility will be expanded to include testing infrastructure for heavy vehicles such as buses and trucks.

Beyond licensing, the complex is also envisioned as a traffic education hub. Agnihotri said it will serve as a practical learning space for school children, helping instill awareness about road safety and traffic rules at an early stage.

Announcing a broader development push in the area, he said Rs 10 crore will be invested to transform the Rora ground into a permanent venue for fairs and festivals. The site recently hosted the state-level Haroli Utsav, which saw strong public participation. Encouraged by the response, the government plans to extend the duration of the festival in the coming years.

Agnihotri also announced that a one-kilometre stretch from the Haroli-Rampur Bridge to the T-junction at Rora will be developed as 'Vikas Path', showcasing developmental works along a modern, well-lit corridor.

Positioning Rora as an emerging urban hub, he said multiple projects are underway, including a Rs 19-crore heliport to enhance air connectivity with Shimla and Chandigarh, and a Rs 10-crore synthetic athletic track. Officials including State Transport Authority Secretary Naresh Thakur and Deputy Commissioner Jatin Lal were present at the event.

हिमाचल,दस्तक, दिनांक–23.04.2026

प्रदेश को मिला पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 9 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को हरोली के रोड़ा में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश को पूर्णतः तकनीक आधारित, पारदर्शी और निष्पक्ष ड्राइविंग टेस्ट प्रणाली मिल गई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया और आरटीओ के इलेक्ट्रिक वाहन में बैठकर ट्रैक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया।

डिप्टी सीएम मुकेश ने कहा कि यह ऑटोमेटेड ट्रैक ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाएगा तथा मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए योग्य अभ्यर्थियों का सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। सेंसर आधारित पूरे ट्रैक में अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से हर गतिविधि की निगरानी रहेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिसर उत्तर भारत का अपनी तरह का इकलौता ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक और ट्रैफिक पार्क है। यहां भविष्य में और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। लोगों की सुविधा के लिए यहां वेटिंग एरिया और भवन का निर्माण किया जाएगा, ताकि खराब मौसम में भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगले चरण में यहां बसों और ट्रकों के लिए भी टेस्टिंग सुविधा विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्रणाली के तहत अभ्यर्थी स्वयं अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट की तिथि और समय निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि, वर्तमान में पुरानी व्यवस्था भी समानांतर रूप से जारी रहेगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग नई प्रणाली को प्राथमिकता दें। उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस आधुनिक ट्रैक में छोटे वाहनों के लिए एस 8 और एच ट्रैक, पैरेलल पार्किंग, जंक्शन ड्राइविंग तथा ढलान पर वाहन संचालन जैसे विभिन्न परीक्षण शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह परिसर डिजिटाइज्ड तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था के अलावा स्कूली बच्चों के लिए एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी विकसित होगा। यहां उन्हें ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति व्यावहारिक जानकारी भी मिलेगी।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रणजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप अग्निहोत्री, राज्य परिवहन प्राधिकरण के सदस्य अशोक ठाकुर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य विवेक मिंका, परिवहन समिति के सदस्य नवीन दत्ता, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश पराशर, कांग्रेस नेता विनोद बिट्टू, हिमकैप्स संस्था के अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह, प्रमोद कुमार, आरटीओ अशोक कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।

हरोली मैदान रोड़ा के विकास को 10 करोड़

उपमुख्यमंत्री ने हरोली मैदान रोड़ा को स्थायी मेला स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित राज्यस्तरीय हरोली उत्सव को लोगों का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में मेले की अवधि भी बढ़ाई जाएगी।

रोड़ा क्षेत्र विकसित नगर के रूप में उभर रहा

अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली का रोड़ा क्षेत्र तेजी से एक विकसित नगर के रूप में उभर रहा है और वर्ष-2027 तक यहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं साकार रूप लेंगी। यहां लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से हेलिपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे भविष्य में शिमला और चंडीगढ़ से सीधी हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा, रोड़ा में 10 करोड़ रुपये की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है।

विकास पथ के रूप में विकसित होगा हरोली-रामपुर मार्ग

उपमुख्यमंत्री ने हरोली-रामपुर पुल से लेकर इस मार्ग के अंतिम छोर तक पूरे रास्ते को विकास पथ नाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मार्ग को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। यहां बेहतर लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरोली-रामपुर पुल और यह पूरा मार्ग पहले ही लोगों के लिए घूमने-फिरने का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बन चुका है। अब यह केवल आवाजाही का रास्ता नहीं है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया है, जहां शाम होते ही लोग सैर और समय बिताने के लिए पहुंचते हैं।

हिमाचल,दस्तक, दिनांक–24.04.2026

एटीएस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिले टैक्सी और ट्रक ऑपरेटर्स

सीएम ने मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा देने का दिया आश्वासन

हिमाचल दस्तक ■ गगल

एटीएस (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) मामले को लेकर बस, टैक्सी एवं ट्रक ऑपरेटर्स की मांगों के संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कांगड़ा एयरपोर्ट पर मुलाकात की।

यह जानकारी उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि कांगड़ा जिले में आरटीओ तथा एमवीआई के माध्यम से भी फिलहाल कमर्शियल वाहनों के लिए मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से भी आग्रह किया कि वे ऑपरेटर्स की समस्याओं को देखते हुए इस मुद्दे की पैरवी केंद्र सरकार के समक्ष करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वाहनों की फिटनेस जांच को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) के माध्यम से अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रदेश में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस अवसर पर कांगड़ा जिला की विभिन्न ऑपरेटर्स यूनियनों के पदाधिकारियों प्रेसिडेंट विक्की पठानिया, करतार पठानिया, मेहर सिंह ठाकुर, मोहिंद्र सिंह, संजय शर्मा, कार्तिक शर्मा, कुलजीत राणा आदि मौजूद रहे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–29.04.2026

कांगड़ा-नगरोटा बगवां में मशीन पास करेगी गाड़ियां

दोनों ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में होगा सभी वाहनों की परीक्षण जांच

कार्यालय संवाददाता-शिमला

■ अन्य जिलों में पहले की तरह मैनुअल होगी गाड़ियों की पासिंग

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और नगरोटा बगवां में आरएलए के तहत सभी वाहनों की परीक्षण जांच एटीएस (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों) के माध्यम से ही की जाएगी। इसके अलावा पूरे राज्य में अभी पहले की तरह की आरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस की जाएगी। प्रदेश सरकार ने वाहन फिटनेस जांच को लेकर राज्यभर में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के तहत अब प्रदेश में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए परीक्षण समानांतर रूप से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों एटीएस और संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज आरटीओ दोनों पर किया जाएगा। हालांकि अभी तक राज्य में कांगड़ा जिला के रानीताल में ही एटीएस बनाया गया है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के कई क्षेत्रों में एटीएस निर्माण का कार्य जारी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पहली अप्रैल, 2026 से जिला कांगड़ा के सभी रजिस्ट्रिंग और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के लिए 'परिवहन' प्रणाली पर मैनुअल फिटनेस टेस्ट की सुविधा बंद कर दी है। कांगड़ा जिला के रानीताल में स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन 16 जनवरी, 2026 से पूरी तरह कार्यरत हो चुका है।

वाहन पोर्टल पर सर्टिफिकेट

अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) आरडी नजीम ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत जिला कांगड़ा और नगरोटा बगवां के रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज को छोड़कर बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश में वाहन फिटनेस जांच एटीएस और आरटीओ दोनों जगहों पर की जा सकेगी। साथ ही, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी को निर्देश दिए गए हैं कि वह 'वाहन' पोर्टल पर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीज द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा तुरंत बहाल करे।

* * *